Dr. Madan Paswan, Assit. Prof.
of History Dept., D.B. College.
Class: B.A. Part-II (Hons.) Paper-IVth.
Topic: The Sequel of the Second World War.

Lecture No. 35.
Date: 31.10.2020

1919 में फ्रांस सुरक्षा के लिए लालायित था। वह वरसाई Versailles की संधि को अक्षरशः लागू करने और जर्मनी से हरजाना वसूल करने के लिए कृतसंकल्प था। जिसके निम्न प्रभाव दिखागया :-

(1) रेमण्ड पुअंकारे की वह नीति 1924 तक अपनाई जाती रही। जर्मनी द्वारा ऋण की अदायगी न करने पर 1923 ई० में रूर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया।

(2) ऋण अदा न करने पर जो नीति अभी तक मिस्र, आटोमन साम्राज्य तथा चीन इत्यादि गैर यूरोपीय देशों पर लागू की जाती थी वह अब पराजित यूरोपीय देश के विरुद्ध भी लागू की गई।

(3) जर्मनी की भूमि पर कब्जा करने के फलस्वरूप जर्मनी और फ्रान्स के सम्बन्धों में कटुता बढ़ने के साथ-साथ फ्रान्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस पहले से भी अधिक अलग-अलग पड़ गया। इतना होने पर भी युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का खर्च पूरा करने के लिए ब्लॉक नेशनल (अथवा- इसमें राजलिस्ट, अनुदार रिपब्लिकन और मिलरां जैसे Socialist शामिल थे। यह दल सामाजिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि पुनः स्थापित करने के वायदे पर सत्ता में आया था।) को, जिसका फ्रान्स की राजनीति पर नियंत्रण था, कराधान का सहारा लेना पड़ा।

(4) मजदूर वर्ग के असंतोष का मुकाबला करने के लिए सरकार ने सैनिक बल का प्रयोग करने में संकोच नहीं किया। फलतः C.G.T. [Confederation Generale du Travail] को भंग कर दिया गया।

1924 में हुए निर्वाचन में वामपक्ष की तथा 'कार्तेल द -गोश Cartel des Gauches अर्थात वामपंथी सन्युक्त मोर्चे की, जिसमें रेडिकल और सोशलिस्ट Socialist शामिल थे, विजय हुई। लेकिन Socialists ने सरकार में शामिल होने से इस डर से इनकार कर दिया कि Communist उन पर प्रतिक्रियावादी बुर्जुआ शासन के साथ सहयोग करने का आरोप आधारित आरोप लगायें। हेरियट

की सरकार के समक्ष कठिन आर्थिक समस्याएँ थीं। आर्थिक संकट पर नियंत्रण करना कठिन हो रहा था। कर में वृद्धि करने और पूँजी पर कर लगाने के विकल्प को आवश्यक समर्थन नहीं मिल सका।

— Dr. Madan Paswan - History.